नासिक श्रमिक संघ

बनाम

हिंदूस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

(सिविल अपील सं 9332-9333/2010)

26 फरवरी, 2016

[दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायाधिपतिगण]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 2 (ए)-उपयुक्त सरकार- अपीलार्थी श्रमिक संघ द्वारा 1971 के अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी कम्पनी के खिलाफ शिकायत -सेवाओं की निरंतरता और पिछले वेतन के साथ प्रशिक्षुओं की बहाली के लिए कंपनी (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड)- उक्त विवाद को संदर्भित करने के लिए उपयुक्त सरकार-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि 1947 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए उपयुक्त सरकार कंपनी के संबंध में केंद्र सरकार है, इस प्रकार, शिकायतें कंपनी के खिलाफ संघ द्वारा दायर किया गया मामला चलने योग्य नहीं था- अभिनिर्धारित किया गयाः प्रत्यर्थी कंपनी के संबंध में उपयुक्त सरकार राज्य सरकार है- गुण-दोष पर नए निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को मामला प्रेषित किया गया -महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन (मान्यता) और अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम, 1971।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 एच॰ए॰एल॰ **2 [**हिंदुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड और अन्य बनाम हिंदुस्तान ऐरोनोटिकल कैंटीन कामगार संघ व अन्य **(HAL2) (2007) 15 SCC 51 -** बाध्यकारी निर्णय नहीं है**]** पहले के फैसले एच॰ए॰एल॰ **1** ⁎**[**हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम कर्मचारी और अन्य **(HAL 1) (1975) 4** एससीसी **679: 1976 (1)** एससीआर पुष्टि की**]** पर ध्यान नहीं दिया है। एच. ए. एल.**1** में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया

गया था कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रयोजन के लिए आईडी अधिनियम के शब्दकोश खंड में पीछे की बात है, यह है राज्य सरकार जिसे संदर्भ बनाना है। एचएएल 2 में न्यायालय ने *** सेल के मामले[भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य बनाम राष्ट्रीय संघ तटवर्ती कार्यकर्ता और अन्य (2001) 7 एस. सी. सी. 1: 2001(2) पूरक एस. सी. आर. 343] में निर्णय का उल्लेख किया है और कहा है कि यह निर्विवाद है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है और यह केंद्र सरकार ही है जो उस पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और इसलिए, उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है। यह विश्लेषण एचएएल 1 और साथ ही सेल के मामले में निर्णय के अनुपात के विपरीत है। इसके विपरीत न तो तथ्यों पर और न ही कानून पर कोई चर्चा हो रही है। यह राय दी गई है कि तथ्य "निर्विवाद" हैं, एचएएल 1 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन के फैसले का उल्लेख किया था। जैसा कि टाटा मेमोरियल अस्पताल श्रमिक संघ मामला में हुआ है , हेवी इंजीनियरिंग मजदूर संघ में प्राधिकरण को सेल में कुछ विचलन के साथ मंजूरी दी गई है। सेल के मामले में प्राधिकरण, जैसा कि निष्कर्ष से पता चलता है, दो स्थितियों को शामिल करता है-अपरिवर्तित प्रावधान और संशोधित प्रावधान। यह एच. ए. एल. 1 में बताए गए सिद्धांतों को बाधित नहीं करता है। इस प्रकार, दो पहलू, पहला, एच. ए. एल. 2 एच. ए. एल. 1 पर ध्यान नहीं देता है और दूसरा, यह निर्विवाद तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ता है जो बताए नहीं गए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एचएएल 2 के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड केंद्र सरकार का एक एजेंट है। एच. ए. एल. 2 ने ध्यान नहीं दिया एच. ए. एल. 1 जिसे सेल के मामले में मंजूरी दी गई थी, इसे एक बाध्यकारी निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, एच. ए. एल. 1 अभी भी अच्छा है और सही कानून निर्धारित करता है और बाध्यकारी है क्योंकि इसकी नींव भारी इंजीनियरिंग मजदूर संघ से प्रवाहित होती है जिसे कुछ

विचलन के साथ सेल में अनुमोदित किया गया था। विचलन वास्तव में अनुमोदन को प्रभावित नहीं करता है। एच. ए. एल. 2 को एक बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सेल के मामले में अनुपात को सही ढंग से लागू नहीं किया और इस प्रकार, पूरे कथन को गलत माना जाना चाहिए।

1.2 यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया है मामले के गुण-दोष के लिए और 2002 के एल. पी. ए. को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह 2006 के एल. पी. ए. को खारिज करने के बाद भी कायम नहीं रहा। चूंकि 2006 के एल. पी. ए. में पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और यह राय दी गई है कि प्रतिवादी कंपनी के संबंध में "उपयुक्त सरकार" राज्य सरकार है, इसलिए मामला गुण-दोष पर नए निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।विवादित आदेश को निरस्त किया गया है।

भारी इंजीनियरिंग मजदूर श्रमिक संघ बनाम बिहार राज्य और अन्य (1969) 1 एससीसी 765: 1970 (1) एस. सी. आर. 995; भारत का खाद्य निगम बनाम परिवहन & डॉक श्रमिक संघ (1999) 7 एस. सी. सी. 59; रमण दयाराम शेट्टी बनाम भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अन्य (1979) 3 एस. सी. सी. 489: 1979 (3) एससीआर 1014; प्रबंध निदेशक, यू. पी. वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन बनाम विजय नारायण वाजपेयी (1980) 3 एससीसी 459: 1980 (2) एससीआर 773 ; राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ बनाम मॉडल मिल्स 1984 पूरक एससीसी 443: 1985 एससीआर 751; भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संघ बनाम भारतीय खाद्य निगम और अन्य (1985) 2 एस. सी. सी. 295: 1985 (3) एस. सी. आर. 150; एयर इंडिया वैधानिक कॉर्प. & अन्य बनाम संयुक्त श्रम संघ और अन्य (1997) 9 एस. सी. सी. 377 : 1996 (9) पूरक एस. सी.

आर. **579**; टाटा मेमोरियल अस्पताल कर्मचारी संघ बनाम टाटा मेमोरियल केंद्र और अन्य **(2010) 8** एस. सी. सी. **480: 2010 (9)** एस. सी. आर. **723** संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

2001 (2) सप्ल. एससीआर 343	संदर्भित	पैरा 5
1970 (1) एससीआर 995	संदर्भित	पैरा 8
1999) 7 एससीसी 59	संदर्भित	पैरा 11
1979 (3) एससीआर 1014	संदर्भित	पैरा 14
1980 (2) एससीआर 773	संदर्भित	पैरा 14
1985 एससीआर 751	संदर्भित	पैरा 17
1985 (3) एससीआर 150	संदर्भित	पैरा 17
1996 (9) पूरक एससीआर 579	संदर्भित	पैरा 17
2010 (9) एससीआर 723	संदर्भित	पैरा 22
1976 (1) एससीआर 231	माना गया	पैरा 26
(2007) 15 एससीसी 51	मानने योग्य निर्णय नहीं	पैरा 26

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. **9332-9333/2010**

रिट याचिका संख्या 3562 /1997 के एलपीए संख्या 144 / 2002 और एलपीए संख्या 84/ 2006 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय और आदेश दिनांक 25.06.2009 से।

अपीलार्थी के लिए कॉलिन गोंजाल्विस, कमलेश कुमार मिश्रा, ज्योति मेंदिरत्ता।

प्रत्यर्थीगण के लिए एस. गुरु कृष्ण कुमार, धनंजय बैजल, एन. साई विनोद, निखिल नैयर।

न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा दिया गया था-

दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति.

1. वर्तमान अपीलों को बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 84/2006 में पारित दिनांक 25.06.2009 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसमें डिवीजन बेंच ने रिट याचिका संख्या 3562/1997 में दिए गए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अमान्य कर दिया है, जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि राज्य सरकार प्रत्यर्थी-कंपनी के उद्देश्य से उसके संबंध में उपयुक्त सरकार है महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन की मान्यता और अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम, 1971 (संक्षेप में, "1971 अधिनियम")।

2. इन अपीलों के निर्णय के लिए जो तथ्य बताए जाने आवश्यक हैं, वे यह हैं कि अपीलार्थी, नासिक श्रमिक संघ ने एक और शिकायत (यूएलपी) संख्या 35 /1990 नासिक वर्कर्स यूनियन ने प्रशिक्षुओं की निरंतरता के साथ सेवाएँ बहाली और पिछला वेतन के लिए दायर की है।

पहली शिकायत के लंबित रहने के दौरान, जैसे ही अन्य कर्मचारियों को छोड़ा गया एक और शिकायत (यूएलपी) संख्या 36/1990 दर्ज की गई। समय बीतने के साथ , शिकायत की विषय वस्तु वाली दो अन्य शिकायतें (यूएलपी) संख्या 44/ 1990 और 45/1990 भी पीठासीन अधिकारी-न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, नासिक के समक्ष पंजीकृत की गईं। श्रम न्यायालय ने रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री की सराहना की, घोषित किया कि नियोक्ता ने कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने में अनुचित श्रम

प्रथाओं में संलग्न था और तदनुसार, सेवा की निरंतरता और पूर्ण बकाया वेतन के साथ कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की तारीख से बहाली तक निर्देश दिया। उक्त आदेश का अनुपालन आदेश दिनांक 08.08.1994 से एक माह के अन्दर किया जाना था।

3. श्रम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश पर संशोधन आवेदन (यू. एल. पी.) संख्या 140/ 1994 और 28-30/ 1995 को औद्योगिक न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया गय। ठाणे में महाराष्ट्र के औद्योगिक न्यायालय ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की और 8 जुलाई, 1997 के आदेश के माध्यम से संशोधन आवेदनों को खारिज कर दिया।

4. श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर 1997 की रिट याचिका संख्या 3562 में चुनौती दिया गया था जिसमें एक तर्क में यह कहा गया कि विवाद के संबंध में "उपयुक्त सरकार" केंद्र सरकार थी न कि राज्य सरकार और इसलिए, 1971 का अधिनियम लागू नहीं होगा और परिणामस्वरूप, श्रमिक संघ द्वारा दायर शिकायतें खारिज किए जाने के योग्य हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलेख पर लाई गई सामग्री की सराहना करते हुए रिट याचिका की स्वीकार की और नियोक्ता को निर्देश दिया कि जब भी नियमित रिक्तियां विचार के लिए आती हैं तो कुछ प्रशिक्षुओं को एक प्रस्ताव दें और यदि वे आवश्यक योग्यता को पूरा करते हैं तो उन्हें नियमित नौकरी के लिए विचार करें।

5. उपरोक्त आदेश को नियोक्ता द्वारा अंतर-न्यायालय अपील को प्राथमिकता देकर चुनौती दी गई थी। हालाँकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने श्रम न्यायालय के साथ-साथ औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया, फिर भी उन्होंने नियोक्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया था कि इसके संबंध में उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार हैकथित तर्क को ज़ोर प्रदान करने के लिए। भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स और अन्य((2001) 7 एस. सी. सी. 1)और अन्य

2001)7 एससीसी 1 पर निर्भरता रखी गई, 'और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड औरअन्य बनाम हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल कैंटीन कामगार संघ और अन्य **(**एच. ए. एल. **2)** '(2007) 15 एस. सी. सी. 51पर भी पर भी। इसके अलावा, सिविल अपील संख्या 5655 /2008 दिनांक 04.12.2008 को पारित आदेश से भी प्रेरणा ली गई।

6. उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए डिवीजन बेंच ने राय दी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, "आईडी अधिनियम ") के उद्देश्य के लिए उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है जो कंपनी के संबंध में उपयुक्त सरकार है और तदनुसार, यूनियन द्वारा कंपनी के खिलाफ दायर की गई शिकायतें सुनवाई योग्य नहीं थीं। इस दृष्टिकोण के कारण, इसने अपील संख्या 84/2006 को अनुमति दी और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को रद्द कर दिया। ज्ञात हो, जैसे ही उच्च न्यायालय अपील संख्या 84 / 2006 में उक्त निष्कर्ष पर पहुंचा, उसने राय दी कि अपील संख्या 144/ 2002 वाली अन्य अपील किसी भी विचार के योग्य नहीं है। उपरोक्त आदेश इन अपीलों में जांच का विषय है।

7. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कॉलिन गोंजाल्विस और प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. गुरु कृष्ण कुमार को सुना है।

8. शुरुआत में, हम यह कहना उचित समझते हैं कि चूंकि खंड पीठ ने मामले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया है और केवल शिकायतों की संधारणीयता के आधार पर अपील का फैसला किया है, इसलिए हम अपने को केवल उक्त पहलू तक ही सीमित रखेंगे। प्रत्यर्थी-कंपनी के संबंध में उपयुक्त सरकार के मुद्दे का एक इतिहास है जो हमें टाइम मशीन में यात्रा करने के लिए मजबूर करता है। चार दशक पहले, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम श्रमिक और अन्य (1975) 4 एस. सी. सी. 679 **(**एच. ए. एल. **1)**, जैसा कि तथ्यों से पता चलता है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच कुछ मुद्दों के निर्णय के लिए आई. डी. अधिनियम की धारा 10

(1) के तहत एक संदर्भ दिया था। न्यायाधिकरण ने श्रमिकों को आंशिक राहत दी थी। उक्त पुरस्कार से दुखी होकर, नियोक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अवकाश द्वारा अपील को प्राथमिकता दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार की संदर्भ देने की क्षमता जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय के समक्ष भी चुनौती किया गया था। यह तर्क दिया गया कि चूंकि केंद्र सरकार कंपनी में शेयरों के पूरे बंडल की मालिक है और निदेशक मंडल के साथ-साथ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति और उन्हें हटा देती है और आगे सभी महत्वपूर्ण मामले भारत सरकार के राष्ट्रपति के निर्णय के लिए आरक्षित हैं और अंततः उनके निर्देशों के अनुसार निष्पादित, यह स्पष्ट है कि कंपनी के स्वामित्व वाले उद्योग को आगे बढ़ाने के मामले में कंपनी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। उस पृष्ठभूमि में यह आग्रह किया गया था कि प्रश्न में औद्योगिक विवाद एक ऐसे उद्योग से संबंधित है जो आईडी अधिनियम की धारा 2 (ए) (आई) के अर्थ के भीतर "केंद्र सरकार के अधिकार के तहत" किया गया था और इसलिए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भ देने वाली एकमात्र उपयुक्त सरकार थी। तीन- न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन बनाम बिहार राज्य और अन्य'[(1969)1 SCC 765] के मामले में एक समान प्रस्तुति दी गई थी जिसे इस न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। ध्यान दें, एचएएल में तीन जजों की बेंच ने हेवी इंजीनियरिंग जी मजदूर यूनियन **(सुप्रा)** के एक अंश को पुन: प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित प्रभाव वाला है:

"यह सच है कि केंद्र सरकार ने पूरी शेयर पूंजी का योगदान करने के अलावा, उसे व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिसमें कंपनी को कैसे काम करना चाहिए, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति और यहां तक कि कंपनी द्वारा उनके कर्मचारी को देय मजदूरी और वेतन निर्धारित करने की शक्ति भी शामिल है। लेकिन ये शक्तियाँ कंपनी के संगठन के ज्ञापन और संगठन के लेखों से प्राप्त होती हैं, न कि कंपनी के केंद्र

सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण। सवाल यह है कि क्या कोई निगम राज्य का एक एजेंट है यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर रहना चाहिए। जहाँ एक निगम की स्थापना करने वाला एक क़ानून इस प्रकार प्रदान करता है, वहाँ ऐसे निगम को आसानी से राज्य के एजेंट के रूप में पहचाना जा सकता है जैसा कि ग्राहम बनाम लोक निर्माण आयुक्त[(1901) 2 के. बी 781: 70 एलजे के. बी. 860: 17 टीएलआर 540]में था, जहाँ न्यायाधिपति फिलिमोर ने कहा कि क्राउन कुछ मामलों में संसद की सहमति से कुछ अधिकारियों या निकायों को स्थापित करता है जिन्हें लोक निर्माण के लिए क्राउन के एजेंट के रूप में माना जाना है। भले ही उनके पास अनुबंध करने की शक्ति प्रिन्सिपल के तौर पर है तथापि, वैधानिक प्रावधान के अभाव में, अपनी ओर से कार्य करने वाले वाणिज्यिक निगम, भले ही यह पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी सरकारी विभाग द्वारा नियंत्रित हो, आमतौर पर यह माना जाएगा कि वे राज्य के सेवक या एजेंट नहीं हैं। तथ्य यह है कि एक मंत्री एक निगम के सदस्यों या निदेशकों की नियुक्ति करता है और उसे जानकारी के लिए कॉल करने, निदेशकों को बाध्यकारी निर्देश देने और निगम के व्यवसाय के संचालन पर निगरानी रखने का अधिकार है, जो निगम को सरकार का एजेंट नहीं बनाता है, (भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापत्तनम [(1964) 4 एससीआर 99। 188: ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1811, द्वारा न्यायाधिपति शाह] और तामलिन बनाम हैनाफोर्ड [(1950) 1 के. बी. 18,25,26] देखें।)। ऐसा निष्कर्ष कि निगम सरकार का अभिकर्ता है, वहां खींचा जा सकता है जहां वह यह वास्तविक रूप से सरकारी कार्य कर रहा है न कि वाणिज्यिक(सी. एफ. लंदन काउंटी प्रादेशिक और सहायक बल एसोसिएशन बनाम निकोल्स) (1948) 2 आल. ई. आर. 432।"

9. हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन (उपरोक्त) के मामले में उक्त फैसले में अंतर करने का प्रयास किया गया था की यह ऐसा मामला था जहाँ सरकारी कंपनी उद्योग चल

रही थी जहाँ निजी क्षेत्र के उपक्रम भी काम कर रहे थे और इसलिए, यह एक ऐसा उद्योग नहीं था जिसे अकेले सरकार निजी ऑपरेटरों के बहिष्कार को जारी रखने की हकदार थी। न्यायालय ने राय दी कि इस प्रकार किए गए भेद का कोई परिणाम नहीं था और इससे पहले के निर्णय के अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न्यायालय ने आगे कहा कि यद्यपि आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (ए) (आई) को समय-समय पर कुछ वैधानिक निगमों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है ताकि केंद्रीय सरकार उनके द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग के संबंध में एक उपयुक्त सरकार है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक कंपनी को, भले ही शेयर विशेष रूप से सरकार के स्वामित्व में हों, उक्त परिभाषा में शामिल करने का प्रयास किया गया था। ज्ञात हो, कि पश्चिम बंगाल सरकार की क्षमता को चुनौती देने के तर्क का दूसरा पहलू यह था कि विवाद बैरकपुर शाखा में उत्पन्न हुआ था जो कंपनी के बैंगलोर डिवीजन के नियंत्रण में था। उक्त निवेदन स्वीकार नहीं किया गया। हम वास्तव में मामले के दूसरे पहलू से चिंतित नहीं हैं, जैसा कि है स्पष्ट रूप से, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंध में, राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है।

10. उक्त मामले में न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त विश्लेषण से , जैसा कि हमने देखा है कि न्यायालय को हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन **(**सुप्रा**)** में बताए गए सिद्धांतों और आईडी अधिनियम की धारा 2 (ए)(i) में निहित प्रावधान द्वारा निर्देशित किया गया है। ने हालांकि केंद्र सरकार को उनके द्वारा चलाए जा रहे उद्योग के संबंध में "उपयुक्त सरकार" बनाने के लिए कुछ परिभाषाएँ शामिल की थीं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक कंपनी को, भले ही शेयर विशेष रूप से सरकार के स्वामित्व में थे, उक्त परिभाषाओं के दायरे में लाने का प्रयास नहीं किया गया था।

11. वर्तमान मामले में, यह समझ में आता है कि डिवीजन बेंच ने सेल के मामले में संविधान पीठ के फैसले के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष

को खारिज कर दिया है। इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष रखे जाने का एक कारण यह था कि खाद्य निगम भारत बनाम परिवहन एवं गोदी श्रमिक संघ [(1999) 7 एससीसी 59] में दो न्यायाधीशों की पीठ थी ने अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (संक्षेप में, "सी. एल. आर. ए. अधिनियम")धारा 2(1)(ए) और आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (ए) में अभिव्यक्ति "उचित सरकार" की व्याख्या पर न्यायालय की दो तीन-न्यायाधीश पीठों सहित विभिन्न पीठों के बीच राय के टकराव को देखा था। वृहद पीठ ने निर्धारण के लिए तीन मुद्दे रखे थे और उनमें से एक था - "सीएलआरए एक्ट की धारा 2 की उप -धारा (1) के खंड (ए) में परिभाषित "उचित सरकार" अभिव्यक्ति का सही और सत्य अर्थ क्या है। ``उक्त बिंदु को आगे बढ़ाते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने माना था कि राज्य सरकार प्रश्न में केंद्र सरकार की कंपनियों की स्थापना के संबंध में उपयुक्त सरकार है। रुख यह था कि 28.01.1986 से सीएलआरएएक्ट में "उचित सरकार" की संशोधित परिभाषा के मद्देनजर केंद्र सरकार "उचित सरकार" होगी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह तर्क दिया गया कि 28.01.1986 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से पहले और बाद में "उपयुक्त सरकार" केंद्र सरकार थी।

12. संविधान पीठ ने सी. एल. आर. ए. अधिनियम,धारा 2 की उप-धारा (1) का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैः

"2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

(क) 'उपयुक्त सरकार' का अर्थ है -

(i) किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में जिसके संबंध में - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14/ 1947), के तहत उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार, केंद्र सरकार है;

(ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, सरकार उस राज्य का जिसमें वह अन्य प्रतिष्ठान स्थित है। न्यायालय ने इसकी अपरिवर्तित परिभाषा पर भी ध्यान दिया

न्यायालय ने धारा 2(ए) में निहित "उचित सरकार " की असंशोधित परिभाषा पर भी ध्यान दिया, उक्त असंशोधित प्रावधान इस प्रकार है:

"2. (1)(ए) 'उपयुक्त सरकार' का अर्थ है

(1) के संबंध में

(i) केंद्र सरकार द्वारा या उसके प्राधिकरण के तहत चलाए जाने वाले किसी भी उद्योग से संबंधित कोई भी प्रतिष्ठान, या संबंधित ऐसे किसी भी नियंत्रित उद्योग के लिए जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा, निर्दिष्ट किया जाए या

(ii) किसी भी रेलवे, छावनी बोर्ड की कोई स्थापना, प्रमुख बंदरगाह, खदान या तेल क्षेत्र, या

((iii) बैंकिंग या बीमा कंपनी का कोई भी प्रतिष्ठान, केंद्रीय सरकार,

(2) किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, उस राज्य की सरकार जिसमें वह अन्य प्रतिष्ठान स्थित है;

13. अपरिवर्तित प्रावधान का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया है

"अपरिवर्तित परिभाषा के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार होगी यदि विचाराधीन प्रतिष्ठान उपखंड (i) से (iii) में दिए गए विवरण का उत्तर देता है। और किसी भी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, राज्य की सरकार, जिसमें विचाराधीन प्रतिष्ठान स्थित है, उपयुक्त सरकार होगी। जहाँ तक उपखंड (ii) और (iii) का संबंध है, वे कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं करते हैं। चर्चा उप-खंड (i) पर केंद्रित है। यह देखा जा सकता है कि उप-खंड (i) के दो अंग हैं। पहला अंग केंद्र सरकार द्वारा या

उसके अधिकार के तहत किए जाने वाले किसी भी उद्योग से संबंधित स्थापना को शामिल करता है और दूसरे अंग में ऐसे नियंत्रित उद्योगों को शामिल किया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा उस संबंध में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।"

14. ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने रमाना दयाराम शेट्टी बनाम भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य[(1979) 3 एस. सी. सी. 489] और प्रबंध निदेशक, यूपी भण्डारण निगम. बनाम विजय नारायण वाजपेई" [(1980) 3 एस. सी. सी. 459] के अधिकारियों को संदर्भित किया, और कई अन्य लोगों ने इस प्रकार राय दी:-

"37, हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि सार्वजनिक कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सरकारी कंपनियों /निगमों/समाजों, जो सरकार की सहायक संस्थाएं या एजेंसियां हैं, को सार्वजनिक कानून-संवैधानिक या प्रशासनिक क्षेत्र में समान सीमाओं के अधीन किया जाना चाहिए। स्वयं सरकार के कानून से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वे सभी उद्देश्यों के लिए केंद्र/राज्य सरकार के एजेंट बन जाते हैं ताकि ऐसी सरकार को विभिन्न केंद्रीय और/या राज्य अधिनियमों या निजी कानून के तहत उनके सभी कार्यों, देनदारियों और दायित्वों के लिए बाध्य किया जा सके।

38. उपरोक्त चर्चा से, यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में केंद्र/राज्य सरकार का साधन होने या "राज्य" होने का तथ्य इस प्रश्न का निर्धारक नहीं हो सकता है कि क्या कोई उद्योग चलाया जाता है एक कंपनी /निगम या सरकार का एक साधन सीएलआरए अधिनियम में उचित सरकार की परिभाषा के अर्थ के भीतर या उसके उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार के अधिकार के तहत या उसके अधीन है। राज्य सरकार निगम/कंपनी का मामला लें राज्य सरकार द्वारा स्थापित और स्वामित्व वाला उपक्रम जो राज्य सरकार का एक साधन या एजेंसी है और एक उद्योग चलाने में लगा हुआ है, क्या यह माना जा सकता है कि उद्योग केंद्र सरकार के अधिकार के तहत चलाया जाता है, और संबंध में उद्योग से संबंधित किसी भी औद्योगिक विवाद

के लिए क्या यह कहा जा सकता है कि उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है? हमारा मानना है कि उत्तर नकारात्मक होना चाहिए..... "

और फिर सेः

"इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि केंद्र सरकार की सभी कंपनियां जिनके साथ हम यहां काम कर रहे हैं, वे केंद्र सरकार के बराबर नहीं हैं और न ही उनकी बराबरी की जा सकती है, हालांकि वे संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" हो सकती हैं। हमने ऊपर कहा है केंद्रीय ई सरकार का साधन या एजेंसी होना अपने आप में उस विशेष उद्योग को चलाने के लिए केंद्र सरकार का अधिकार होना नहीं होगा। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि केंद्र सरकार की किसी कंपनी की स्थापना के संबंध में/ उपक्रम, उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार होगी। यह मानने के लिए कि केंद्र सरकार किसी प्रतिष्ठान के संबंध में "उचित सरकार" है, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि प्रश्न में विशेष उद्योग उसके अधिकार के तहत या केंद्र सरकार के अधीन चलाया जाता है। यदि इस पहलू को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्र सरकार सीएलआरए अधिनियम और आईडी अधिनियम के तहत "उचित सरकार" होगी, बशर्ते कि संबंधित उद्योग केंद्रीय सरकार की कंपनी/उपक्रम के अधिकार के तहत चलाया जाता हो। ऐसा अधिकार या तो क़ानून द्वारा या प्रिंसिपल और एजेंट के रिश्ते या शक्ति के प्रतिनिधिमंडल के आधार पर प्रदान किया जा सकता है। जहाँ अधिकार केंद्र सरकार के लिए या उसकी ओर से है, किसी भी उद्योग को चलाने का, सरकारी कंपनी/कानून द्वारा कोई भी उपक्रम जिसके तहत उसे बनाया जाता है, आगे कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या कोई अधिकार सरकारी कंपनी/केंद्र द्वारा किसी भी उपक्रम पर प्रदान किया गया है। यह प्रश्न तथ्य का और तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ में सुनिश्चित किया जाना है।" [जोर दिया गया]

15. ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने "उपयुक्त सरकार" की संशोधित परिभाषा को स्वीकार कर लिया जिसका वही अर्थ है जो आई. डी. अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए) में दिया गया है। संशोधित प्रावधान में निर्णय का उल्लेख करने के बाद, यह नोट किया गया कि यह वाक्यांश "केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत चलाया जाने वाला कोई भी उद्योग" अपरिवर्तित और संशोधित परिभाषा दोनों में एक सामान्य कारक है। विभिन्न पहलुओं की ओर बढ़ते हुए, दीर्घ पीठ ने हेवी इंजीनियरिंग मजदूर संघ में निर्णय का उल्लेख किया (ऊपर) और उस संदर्भ में, उक्त निर्णय के कारणों की सराहना करने के बाद, इसने इस प्रकार कहा हैः

" ..... इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उपयुक्त सरकार के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि केवल यह तथ्य कि संपूर्ण शेयर पूंजी का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और यह तथ्य कि इसके सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति के पास थे और केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह माना गया कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में, अपनी ओर से कार्य करने वाला एक वाणिज्यिक निगम, भले ही वह पूरी तरह या आंशिक रूप से, एक सरकारी विभाग द्वारा नियंत्रित हो, आमतौर पर राज्य का सेवक या एजेंट नहीं माना जाएगा। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया था कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निगम सरकार का एजेंट था, जहाँ यह वास्तविक रूप से सरकारी कार्य कर रहा था, न कि वाणिज्यिक कार्य। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, सरकार द्वारा स्थापित और स्वामित्व वाली सरकारी कंपनियों की सरकारी गतिविधि और वाणिज्यिक कार्य के बीच अंतर से सहमत होना मुश्किल है, जहां तक उनके कार्य की बात है, उनके कार्य में सार्वजनिक कानून के क्षेत्र का संबंध है...."

16. उक्त निर्णय का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने एच. ए. एल. 1 में निर्णय को स्वीकार किया और इस प्रकार राय दीः

" .....सी. एल. आर. ए. अधिनियम की धारा 2 में "उपयुक्त सरकार" और "स्थापना" शब्दों की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालत के साथ वजन करने वाले कारक अप्रासंगिक थे। इसमें यह भी बताया गया था कि समय-समय पर कुछ वैधानिक निगमों को परिभाषा में शामिल किया गया था, लेकिन किसी भी सार्वजनिक कंपनी को परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था, जिसके शेयर विशेष रूप से सरकार के स्वामित्व में थे। हेवी ईंजीनियरिंग मामला (ऊपर) समान रूप से क्रियान्वित होगा।"

17. यह ध्यान दिया जाए कि न्यायालय ने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ बनाम मॉडल मिल्स [1984 सप. एस. सी. सी. 443] और भारत का फूड कॉर्प श्रमिक संघ बनाम खाद्य निगम [(1985) 2 एससीसी-294] में अधिकारियों को संदर्भित किया।एयर इंडिया सांविधिक निगम और अन्य बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन और अन्य [(1997) 9 एस. सी. सी. 377] में क्या कहा गया है, यह बताने के लिए आगे बढ़े, यानी सी. एल. आर. ए. अधिनियम की शुरुआत से, "उपयुक्त सरकार" केंद्र सरकार थी और उसके बाद, राय दी किः

"हमने ऊपर माना है कि केंद्र सरकार की कंपनी/उपक्रम , सरकार का एक साधन, उद्योग चलाने के मामले में, यह निर्धारित करने का मानदंड है कि केंद्र सरकार सीएलआरएएक्ट के अर्थ के भीतर उपयुक्त सरकार है या नहीं। उद्योग को केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत चलाया जाना चाहिए और यह नहीं कि कंपनी/उपक्रम संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार की एक संस्था या एजेंसी है; ऐसा अधिकार किसी क़ानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है या प्रिंसिपल और एजेंट के रिश्ते या शक्ति के प्रतिनिधिमंडल के आधार पर और इस तथ्य को प्रत्येक मामले के

तथ्यों और परिस्थितियों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, उचित सम्मान के साथ, हम इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं एयर इंडिया मामले (सुप्रा) में अभिव्यक्ति "उचित सरकार" की व्याख्या पर विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किया गया। बिंदु (i) का तदनुसार उत्तर दिया गया है।"

18. उपरोक्त पहलू के संबंध में निष्कर्षों का सारांश देते हुए, इसे इस प्रकार निर्धारित किया गया हैः

"(1) (a) 28-1-1986 से पहले, इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी प्रतिष्ठान के संबंध में उपयुक्त सरकार है, सी. एल. आर. ए. अधिनियम में "उपयुक्त सरकार" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, एक और प्रश्न के उत्तर पर, क्या विचाराधीन उद्योग केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत चलाया जाता है या क्या यह किसी निर्दिष्ट नियंत्रित उद्योग, या किसी रेलवे, छावनी बोर्ड, प्रमुख बंदरगाह, खदान या तेल क्षेत्र की स्थापना या बैंकिंग या बीमा कंपनी की स्थापना से संबंधित है? अगर जवाब सकारात्मक रूप से, केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार होगी; अन्यथा किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में उस राज्य की सरकार जिसमें प्रतिष्ठान स्थित था, वह उपयुक्त सरकार होगी।

(b) उस अभिव्यक्ति की नई परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उक्त तिथि के बाद, ऊपर निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए) में पाया जाना चाहिए; यदि (i) संबंधित केंद्र सरकार की कंपनी/उपक्रम या इसमें कोई भी संबंधित उपक्रम शामिल है, या (ii) कोई भी उद्योग (क) केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत, या (ख) किसी रेलवे कंपनी द्वारा, या (ग) किसी निर्दिष्ट नियंत्रित उद्योग, तब केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार होगी; अन्यथा किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, उस राज्य की सरकार जिसमें वह अन्य प्रतिष्ठान स्थित है, उपयुक्त सरकार होगी।"

19. उपरोक्त विचार-विमर्श के आधार पर, यह अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोंजाल्विस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक प्रत्यर्थी कंपनी का सवाल है, वास्तव में यह केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया जाता है और न ही यह केंद्र सरकार की ओर से उद्योग को चलाने के लिए अधिकृत है और उक्त तर्क को न तो संविधान पीठ द्वारा बदला गया है और न ही पलटा गया है। इसके विपरीत, श्री गोंजाल्विस द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि एच. ए. एल. 1 (उपर्युक्त) में व्यक्त विचार की पुष्टि संविधान पीठ द्वारा की गई है। उनके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि संशोधित प्रावधान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रकृति और चरित्र को नहीं बदलता है क्योंकि परिभाषा से इस तरह के निगम दायरे में नहीं आते हैं।

20. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने एच. ए. एल. **2 (**ऊपर**)** में प्राधिकरण से प्रेरणा ली है। उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया हैः

"इस मामले में विचार के लिए जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना उचित ठहराया था कि संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार "उपयुक्त सरकार" है। संविधान पीठ ने हाल ही में सेल बनाम में अनुबंध श्रम विनियमन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया है। नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स (ऊपर) और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि "उपयुक्त सरकार" वह सरकार होगी जो संबंधित संगठन पर नियंत्रण और अधिकार का प्रयोग करती है। यह निर्विवाद है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड केंद्र सरकार का एक उपक्रम है और यह केंद्र सरकार है जो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस जारी करना इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई मानदंड नहीं है कि राज्य सरकार उचित सरकार है, इसलिए उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय, इसके बावजूद, इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए गलत है जिसका

उल्लेख पहले किया गया था। इसलिए हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करते हैं और मानते हैं कि केंद्र सरकार "उपयुक्त सरकार" है।"

21. जैसा कि हम पाते हैं, उपरोक्त निर्णय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। यह केंद्र सरकार है जो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और इसलिए, केंद्र सरकार " उचित सरकार "। प्रतिवादी कंपनी का रुख यह है कि वह कॉन्ट्रल सरकार की अनुमति के तहत संप्रभु कार्यों पर काम करती है और एचएएल **1** (सुप्रा) में कुछ ज़रूरी पहलू पर विचार नहीं किया गया था और एचएएल **2 (**उपर्युक्त) में किया गया विश्लेषण सही और कानूनी रूप से उचित है। सेल के मामले में, यह कहा गया है कि प्रतिवादी कंपनी केंद्र सरकार के अधिकार के तहत अपना संचालन करती है, क्योंकि उसे केन्द्र सरकार द्वारा शक्ति प्रदान की गई है और अनुमति दी गई है और इसलिए, यह माना जाएगा कि अनुमति विज्ञापन प्रतिवादी कंपनी को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी, यह स्पष्ट करते हुए कि प्रतिवादी कंपनी केन्द्रीय सरकार के अधीन है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 95 की धारा 2 में प्रावधान किया गया है, संघ द्वारा नियंत्रण की अनिवार्यता, यह जनहित में समीचीन है कि संघ को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों को अपने नियंत्रण में ले। प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पहली अनुसूची की प्रविष्टि 7(1) की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो विमान से संबंधित है और प्रविष्टि 37 जो रक्षा उद्योग - हथियार और गोला-बारूद से संबंधित है और , उस आधार पर प्रस्तुत करती है कि प्रतिवादी कंपनी विशिष्ट निर्माता है इसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में माना जाना चाहिए। प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया था कि एचएएल **(**सुप्रा**)** में, न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि प्रतिवादी कंपनी शक्ति प्रदान करने, प्रदान करने, या प्रत्यायोजन करने या अनुमति देने के आधार पर और उसके अनुसरण में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार , और इसलिए, उक्त निर्णय कानून के

वास्तविक प्रस्ताव को नहीं बताता है। यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सेल (सुप्रा) में निर्धारित परीक्षण को सही ढंग से लागू किया है और इसलिए, यह बिल्कुल त्रुटिहीन है। उक्त पहलू पर प्रकाश डालते हुए, यह है उन्होंने तर्क दिया कि एचएएल I (सुप्रा) में निर्णय अनुचित है।

22. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा हमारा ध्यान टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वर्कर्स यूनियन बनाम टाटा मेमोरियल सेंटर और अन्य की ओर भी आकर्षित किया गया है। उक्त मामले में, यह माना गया है कि पहले प्रतिवादी-प्रतिष्ठान के लिए केंद्र सरकार 1971 अधिनियम धारा 2(3) के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त सरकार थी। 1971 अधिनियम के आवश्यक और प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आईडी अधिनियम की धारा 2(1) का उल्लेख किया और कहा कि परिभाषा से यह स्पष्ट है कि आईडी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार "उचित सरकार" है। "धारा 2((a)(i) के तहत निर्दिष्ट उद्योगों से संबंधित औद्योगिक विवादों के संबंध में और केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत चलाए जाने वाले उद्योगों के संबंध में। उद्योगों की इन दो श्रेणियों को छोड़कर किसी भी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में, राज्य सरकार ही "उचित सरकार" है। न्यायालय ने "कोई भी" वाक्यांश का उल्लेख किया केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत चलाया जाने वाला उद्योग। कोर्ट ने सवाल उठाया- क्या उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच कोर्ट ने सेल के मामले में निर्धारित कानून को सही ढंग से लागू किया है। न्यायालय ने देखा कि सेल के मामले में फैसले ने हैवी इंजीनियरिंग मजदूर संघ (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को दोहराया है, हालांकि थोड़ा सा विचलन और यह जांच करना उचित समझा कि न्यायालयों द्वारा "उपयुक्त सरकार" की अवधारणा को बाद में अग्रणी निर्णयों में कैसे समझाया गया है। न्यायालय ने हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन (ऊपर) और एच. ए. एल. 1 (ऊपर) में बताए गए सिद्धांतों का विश्लेषण किया। इसने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (ऊपर) और एयर इंडिया

वैधानिक निगम(ऊपर) सहित विभिन्न प्राधिकरणों में प्राधिकरण का भी उल्लेख किया। इसके बाद न्यायालय ने सेल के मामले के पैराग्राफ 37 से 41,43,45 और 46 को संदर्भित किया और पक्षों के लिए विद्वान वकील की दलीलों को नोट किया और इस प्रकार निर्णय लियाः

"57. वैधानिक ढांचे को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि जब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत शासित किसी उद्योग को एमआरटीयू अधिनियम के तहत कवर करने की बात आती है, तो राज्य सरकार को किसी के संबंध में "उचित सरकार" होना होगा ऐसे उद्योग से संबंधित औद्योगिक विवाद। जैसा कि एमआरटीयू अधिनियम की धारा 2(3) में प्रदान किया गया है, हमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "उद्योग" "उपयुक्त सरकार" की परिभाषाओं पर निर्भर रहना होगा। धारा 2(a) की योजना के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम की, उप-धारा (i) में निर्दिष्ट उद्योगों से संबंधित औद्योगिक विवादों के लिए, और उन उद्योगों के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत चलाए जाते हैं, केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है। धारा 2 (ए)(i) प्रावधान करता है कि "किसी भी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में" राज्य सरकार "उपयुक्त सरकार " है। इसलिए निर्दिष्ट उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों से संबंधित औद्योगिक विवादों में यह जांचना आवश्यक हो जाता है कि क्या उद्योग केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, या केंद्र सरकार के अधिकार के तहत। जब यह दोनों में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, तो राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार होगी।"

X X X X X

59. जहां तक "केंद्र सरकार द्वारा संचालित" उद्योग का सवाल है, तो इसमें ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका मतलब रेलवे या डाक और तार जैसे उद्योग होंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाए जाते हैं। अपने आप। कठिनाई उस उद्योग को तय करते समय उत्पन्न होती है जो "केंद्र सरकार के अधिकार

के तहत" नहीं बल्कि चलाया जाता है। अब, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सेल (सुप्रा) में संविधान पीठ के फैसले में, पहले के चार निर्णयों में विभिन्न पीठों के दृष्टिकोण को विशेष रूप से अनुमोदित किया गया है और एयर इंडिया (सुप्रा) में व्यक्त दृष्टिकोण से असहमति जताई गई है। वाक्यांश "प्राधिकरण के अधीन" हेवी इंजिनीरिंग (उपर्युक्त) में व्याख्या की गई, उसका अर्थ है "प्राधिकारी के अनुसार" जैसे कि जहां कोई अभिकर्ता या सेवक अपने प्रधान या स्वामी के अधिकार के तहत कार्य करता है। यह स्पष्ट रूप से कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी के बारे में नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि हेवी इंजिनीरिंग मजदूर संघ मामला (ऊपर) में निर्धारित किया गया है। हालांकि, जहां एक निगम की स्थापना करने वाला कानून विशेष रूप से प्रदान करता है, वह आसानी से राज्य के एजेंट के रूप में पहचाना जा सकता है।

60. हेवी इंजिनीरिंग मजदूर संघ (उपर्युक्त) ने पाया कि यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि एक निगम सरकार का एक एजेंट था, जहां वह सरकारी और गैर-वाणिज्यिक कार्य में प्रदर्शन कर रहा था। सेल मामले (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने अपने फैसले के पैरा 41 में इस दृष्टिकोण से असहमति जताई है। इसलिए, एक निगम जो वाणिज्यिक गतिविधियों को चला रहा है, वह भी किसी भी स्थिति में राज्य का प्रतिनिधि हो सकता है। हेवी इंजिनीरिंग (उपर्युक्त) निर्णय अन्यथा पूरी तरह से अनुमोदित है, जहां इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि निगम के सदस्य या निदेशक और वह जानकारी के लिए कॉल करने के हकदार हैं, कार्यप्रणाली के संबंध में निर्देश देने के लिए, जो निदेशकों के लिए बाध्यकारी हैं और निगम के व्यवसाय के संचालन की निगरानी करने के लिए निगम को सरकार का प्रतिनिधि नहीं बनाता है। तथ्य यह है कि पूरी निवेश केंद्र सरकार द्वारा योगदान किया जाता है और मजदूरी और वेतन इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यह भी प्रासंगिक नहीं माना गया था।"

23. इस स्तर पर, हम लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि सेल (सुप्रा) में संविधान पीठ थोड़े मतभेद के साथ हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन (सुप्रा) में व्यक्त विचार से सहमत है। इसे निम्नलिखित तरीके से समझाया गया है:

"45. सेल मामले (सुप्रा) में फैसले के पैरा 41 में, संविधान पीठ ने हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन मामले (सुप्रा) में फैसले की जांच की। हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन (सुप्रा) में न्यायालय ने देखा था कि एक निष्कर्ष निगम सरकार का एजेंट था , जहां यह वास्तविक रूप से सरकारी कार्य कर रहा था, न कि वाणिज्यिक कार्य। संविधान पीठ इस प्रकार सरकारी गतिविधि और सरकारी कंपनियों के वाणिज्यिक कार्य के बीच किए गए अंतर से असहमत थी। इस सीमित असहमति को छोड़कर, हालांकि संविधान पीठ ने कहा के पैरा 41 का अंत में, यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने सही सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार "उपयुक्त सरकार" थी और इसका सही जवाब दिया। पैरा 42 में, संविधान पीठ ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (ऊपर) के फैसले की जांच की। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स मजदूर यूनियन मामले (ऊपर) का पालन किया गया था और इस बात पर ध्यान दिया कि अगर बैरकपुर में औद्योगिक शांति में कोई गड़बड़ी होती है, तो "उपयुक्त सरकार" पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए चिंतित थी। न्यायालय ने कहा कि जिन कारकों ने न्यायालय को प्रभावित किया है, उन्हें अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है।

24. यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ एच. ए. एल. 1 (ऊपर) को संदर्भित किया गया और इस प्रकार निर्णय किया गया:

"हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (सुप्रा) में यह तथ्य कि औद्योगिक विवाद पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुआ था और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल मामले में "उपयुक्त सरकार" पश्चिम बंगाल थी, को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के लिए संदर्भित

निर्णय करने के लिए प्रासंगिक माना गया था। राष्ट्रीय मिल मजदूर मामले (सुप्रा) में यह तथ्य कि उपक्रम की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नियंत्रक को नियुक्त किया गया था,यह निर्णय किया गया था कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तथ्य कि उसे केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत काम करना था, यह माना गया कि औद्योगिक उपक्रम को केंद्र सरकार का एजेंट नहीं बनाएगा।"

25. इस प्रकार, जैसा कि स्पष्ट है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वर्कर्स यूनियन (ऊपर) में न्यायालय ने सेल (ऊपर) में प्रस्तावों का विश्लेषण किया था, और मत लिया गया कि कि इसे तथ्यों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए और केवल इसलिए कि सरकारी कंपनियां/ निगम और सोसायटी सार्वजनिक कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो उन्हें केंद्र या राज्य सरकार का एजेंट नहीं बनाता है। आगे यह निर्णय दिया गया है कि उद्योग या उपक्रम को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकार के तहत चलाया जाना चाहिए और यह अधिकार या तो एक क़ानून द्वारा या प्रिंसिपल और एजेंट के रिश्ते, या शक्ति के विधान के आधार पर प्रदान किया जा सकता है। उसमें यह भी देखा गया है कि जब क़ानून द्वारा शक्ति प्रदान करने की बात आती है, तो अधिक कठिनाई नहीं होती है, हालाँकि, जहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ उपक्रम प्राधिकरण के तहत कार्य कर रहा है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है।

26. मौजूदा मामले में, जो मुद्दा विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या एचएएल **2** (सुप्रा) में निर्णय को बाध्यकारी मिसाल माना जा सकता है। जैसा कि ध्यान देने योग्य है, एचएएल **2** (सुप्रा) ने एचएएल **1** (सुप्रा) में पहले के निर्णय पर ध्यान नहीं दिया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रयोजन के लिए आईडी अधिनियम के शब्दकोश खंड के संबंध में एचएएल **1** (सुप्रा) में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, यह राज्य सरकार का संदर्भ है। एचएएल **2** (सुप्रा) में न्यायालय ने सेल के मामले में निर्णय का उल्लेख किया है और राय दी है कि यह

निर्विवाद है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड केंद्र का उपक्रम है सरकार और यह केंद्र सरकार है जो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और इसलिए, उपयुक्त सरकार केंद्रीय सी सरकार है। यह विश्लेषण एचएएल **1 (**सुप्रा**)** और साथ ही सेल के मामले में निर्णय के अनुपात के विपरीत है। इसके विपरीत न तो तथ्यों पर और न ही कानून पर कोई चर्चा हो रही है। यह राय दी गई है कि तथ्य एचएएल **1 (**सुप्रा**)** में "निर्विवादित" हैं, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन (सुप्रा) में निर्णय का उल्लेख किया था। जैसा कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वर्कर्स यूनियन **(**सुप्रा) में हुआ है, हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन **(**सुप्रा**)** में अधिकार रहा है कुछ भिन्नताओं के साथ SAIL (सुप्रा) में अनुमोदित। सेल में प्राधिकरण' मामला, जैसा कि निष्कर्ष से पता चलता है, दो स्थितियों को शामिल करता है - ग़ैरसंशोधित प्रावधान और संशोधित प्रावधान। यह एचएएल **1 (**सुप्रा**)** में बताए गए सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। इस प्रकार, दो पहलू हैं, पहला, एचएएल **2(**सुप्रा**)** एचएएल **I (**सुप्रा**)** पर ध्यान नहीं देता है और दूसरा, यह उन निर्विवाद तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ता है जो बताए नहीं गए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एचएएल **2 (**सुप्रा**)** के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताए कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड केंद्र सरकार का एजेंट है। हमारी सुविचारित राय में, चूँकि **HAL 2** (सुप्रा**)** ने **HAL I** (सुप्रा) पर ध्यान नहीं दिया है, जिसे **SAIL** के मामले में अनुमोदित किया गया है, इसे एक बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता है।इसलिए, हम मानते हैं कि एचएएल । (सुप्रा) अभी भी अच्छा है और सही कानून बनाता है और हम इससे बंधे हैं क्योंकि इसकी नींव हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन **(**सुप्रा**)** से आती है जिसे सेल **(**सुप्रा**)** में कुछ मतभेदों के साथ मंजूरी दे दी गई है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वर्कर्स यूनियन **(**सुप्रा**)** में कहा गया है। चाहे जी ने कहा हो, कि विचलन वास्तव में अनुमोदन को प्रभावित नहीं करता है। हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि एचएएल **2 (**सुप्रा**)** को बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा

सकता। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सेल के मामले में अनुपात को सही ढंग से लागू नहीं किया है और इसलिए, पूरे विश्लेषण को गलत माना जाएगा।

27. विवाद यहीं खत्म नहीं होता। यह माना जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने मामले की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया और एल.पी.ए. संख्या 144 /2002 को खारिज कर दिया, इस आधार पर कि एल.पी.ए. संख्या 84 / 2006 की ख़ारिज होने के बाद यह जीवित नहीं रहा। जैसा कि हमने एल.पी.ए.संख्या 84 / 2006 में पारित आदेश को रद्द कर दिया है। और राय दी गई कि प्रतिवादी कंपनी के संबंध में "उचित सरकार" राज्य सरकार है, मामले को गुण-दोष के आधार पर नए निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए।

28. नतीजतन, अपीलें स्वीकार की जाती हैं और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और एल.पी.ए. 2002 की संख्या 144 को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। हम उच्च न्यायालय से छह महीने के भीतर मामले का निस्तारण करने का अनुरोध करते हैं। हर्जे के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपीलों को स्वीकार किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अर्जिता सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।